जोधपुर-पाली इंडस्ट्रियल एरिया से औद्योगिक क्षमता में बड़ा विकास होगा- भजनलाल

परियोजना के फेज़ ए की टेंडर प्रक्रिया, फेज़ बी की अधिग्रहण सुनवाई का काम पूरा हो गया

जोधपुर/जयपुर, 8 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन से प्रदेश की औद्योगिक क्षमता का निरंतर विकास हो रहा है। उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश स्वर्णिम भविष्य की रेखाएं थार की धरती पर खिंच रही है। यहां जोधपुर और पाली के बीच बसने वाला 'जोधपुर-पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए)' देश का एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बनने की ओर अग्रसर है। यह शहर विकास, निवेश और नवाचार का अद्भुत संगम होगा।

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयास से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अधीन यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान को भारत के औद्योगिक नक्शे पर एक नया मुकाम देने जा रही है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) के सहयोग से रोहट और कांकाणी के मध्य जेपीएमआईए को लगभग 3286 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इसका स्वरूप किसी साधारण औद्योगिक क्षेत्र का नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में होगा, उद्योग, व्यापार, आवास और अवसंरचना का एकीकृत मॉडल शामिल होगा। यहां पहले चरण (फेज-ए) के अंतर्गत 465 करोड़ रुपये की लागत से 642 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

रीको और एनआईसीडीसी के साझा उपक्रम राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (रिडको) के माध्यम से यहां कार्य तेजी से किया जा रहा है। फेज-ए के अंतर्गत 642 हेक्टेयर में निर्माण प्रारंभ के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं, फेज-बी के लिए 1086 हेक्टेयर के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है एवं भूमि अवाप्ति अवार्ड जारी होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके साथ ही फेज-सी में इस परियोजना के तहत वर्ष 2028 तक 1373 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार प्रस्तावित है।

- **इस औद्योगिक क्षेत्र के 31 हेक्टेयर में आवासीय क्षेत्र, 16 हेक्टेयर में वाणिज्यिक ज़ोन तथा 57 हेक्टेयर में सोलर पार्क होगा। इससे नया औद्योगिक शहर पर्यावरण-संतुलित और आत्मनिर्भर भी बनेगा।**

जेपीएमआईए परियोजना के प्रथम चरण में कुल 1279 औद्योगिक प्लॉट प्रस्तावित हैं, जिनमें 435 छोटे, 615 मध्यम और 229 बड़े उद्योग शामिल हैं।

इस औद्योगिक क्षेत्र से स्थानीय स्तर पर 55 हजार प्रत्यक्ष और 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। साथ ही, 31 हेक्टेयर में आवासीय क्षेत्र, 16 हेक्टेयर में वाणिज्यिक ज़ोन, और 57 हेक्टेयर में सोलर पार्क इस औद्योगिक शहर को पर्यावरण-संतुलित और आत्मनिर्भर भी बनाएंगे।

इस परियोजना के लिए रिडको विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) का गठन 51:49 के अनुपात में किया गया है, जिसके अंतर्गत रीको भूमि का योगदान देगा और एनआईसीडीसी आधारभूत संरचना का विकास करेगा। इस औद्योगिक शहर की अनुमानित कुल लागत लगभग 4 हजार 380 करोड़ रुपये है।

परियोजना के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से 48 एमएलडी पानी स्वीकृत किया गया है। इसके लिए 155.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, कांकाणी उपकेन्द्र से बिजली आपूर्ति हेतु 87.21 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। वहीं, अंडरपास और लॉजिस्टिक हब के कार्य वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति के लिए बीएड की बाध्यता क्यों?

जयपुर, 8 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वाइस प्रिंसिपल व प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के लिए बीएड की बाध्यता को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से पूछा है कि क्यों न इस संबंध में बनाए नियम को रद्द कर दिया जाए। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश चित्रकला विषय के व्याख्याता संजय कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- **हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा**

याचिका में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह यदुवंशी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं के पास चित्रकला में पीजी की डिग्री है और उन्हें इस डिग्री के आधार पर ही व्याख्याता पद पर नियुक्ति मिली है। चित्रकला विषय में बीएड भी नहीं होता है। इसके अलावा पदोन्नति से भरे जाने वाले ये दोनों पद प्रशासनिक पद होते हैं। ऐसे में इन पदों पर पदोन्नति के लिए बीएड की योग्यता का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही वाइस प्रिंसिपल व प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नित के लिए बीएड की योग्यता को बाध्यकारी बनाना संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 की अवहेलना करने के साथ ही असंवैधानिक भी है। इसलिए सेवा नियमों के इस प्रावधान को खत्म किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा एनकाउंटर में दो आतंकी मारे

श्रीनगर, 08 नवंबर। कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सैनिकों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में दो आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार, 7 नवंबर को एजेंसियों को घुसपैठ के संबंध में इनपुट मिला। जिसके बाद कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया।

सर्च ऑपरेशन के दौरान सतर्क सैनिकों ने इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी और तुरंत सावधान हो गए। आतंकियों का पता चलते ही जवानों ने पॉजिशन ले ली और उन्हें घेर लिया. जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

कुपवाड़ा में जारी मुठभेड़ को सेना ने ऑपरेशन पिंपल नाम दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि सेना के श्रीनगर में मौजूद चिनार कोर ने बताया कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसके बाद सर्च अभियान शुरू किया गया।

- **सर्च ऑपरेशन में घुसपैठ की कोशिश करते पकड़े जाने पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की।**

इलाके में जब जवानों ने संदिग्ध हरकत देखी तो उन्होंने आतंकियों को चुनौती दी, जिसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि मौके पर सेना के जवानों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। मौजूदा समय में इलाके में ऑपरेशन पिंपल जारी है।

दिल्ली पुनः प्रदूषण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। चीन ने वर्ष 2013 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के अभियान के तहत "प्रदूषण के खिलाफ युद्ध" की घोषणा की थी और इसके तहत कई कड़े कदम उठाए थे, जैसे घनी आबादी वाले इलाकों से कारखानों का स्थानांतरण, वाहनों के उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण, भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करना और कोयले के बजाय प्राकृतिक गैस से ऊर्जा की ज़रुरत पूरी करना। देश ने पुनर्नवीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ज़ोर दिया, जिसके तहत "ग्रेट ग्रीन वॉल" जैसी ऐतिहासिक पहल शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 12 प्रांतों में 35 अरब पेड़ लगाए गए। "अर्थ ऑर्ग" के आँकड़ों के अनुसार, चीन का प्रति हेक्टेयर वनीकरण खर्च अमेरिका और यूरोप से अधिक था और यह वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना था। पिछले दस वर्षों में चीन ने सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में भी जबरदस्त वृद्धि की और इसे अपने औद्योगिक ढाँचे में शामिल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बीजिंग में अब हर साल औसतन 100 अतिरिक्त दिन साफ़ आसमान रहता है, जो पहले संभव नहीं था।

भारतीय संदर्भ में चीन ने अपने अनुभव साझा करने की पेशकश करते हुए कहा है, बीजिंग और शंघाई जैसे प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद, चीन अब गंभीर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। भारत में चीनी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चीन भी कभी गंभीर स्मॉग से जूझ चुका है। हम अपना अनुभव और सफर साझा करने को तैयार हैं, और हमें विश्वास है कि भारत भी जल्द ही नीले आसमान तक पहुँचेगा।

मोदी 11-12 को भूटान जायेंगे

नयी दिल्ली, 8 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 नवंबर को भूटान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर जायेंगे। उस दौरान वे भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के साथ अलग-अलग उच्च स्तरीय बैठक करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने शनिवार को मोदी के भूटान यात्रा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के विशेष संबंधों को मजबूत करना है। यह यात्रा दोनों पक्षों के बीच नियमित उच्च स्तरीय बैठकों की परंपरा का हिस्सा है।

मोदी इस यात्रा में भूटान नरेश से मुलाकात करने के अलावा, उनके साथ दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-दो जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे।

प्रधानमंत्री भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। वे भूटान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी करेंगे।

- **वे जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे।**

प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐसे समय हो रही जब भारत से भूटान भेजे गए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की वहां प्रदर्शनी चल रही है। वह राजधानी थिम्पू के ताशिछोद्जोंग में पवित्र अवशेषों की पूजा-अर्चना करेंगे और भूटान की शाही सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भाग लेंगे।

विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और भूटान के बीच एक अद्वितीय और अनुकरणीय साझेदारी है जो एक-दूसरे के प्रति गहरे आपसी विश्वास, सद्भावना और सम्मान पर आधारित है। दोनों देशों की साझा आध्यात्मिक विरासत और लोगों के बीच मधुर संबंध भारत-भूटान विशेष साझेदारी की पहचान हैं।

लश्कर का आतंकी मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया

आतंकी सलीम खान मुजफ्फराबाद कैंप में ट्रेनिंग ले चुका था

मुंबई, 08 नवंबर। मुंबई एयरपोर्ट से लश्कर ए तैयबा का एक संदिग्ध आतंकी सलीम खान गिरफ्तार किया गया है। सलीम लश्कर के मुजफ्फराबाद कैंप में ट्रेनिंग भी ले चुका है। सलीम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला है। ये आतंकी फैजाबाद से पकड़े गए आईएसआई एजेंट आफताब का फाइनेंसर है।

उसने सेना की मुखबिरी के लिए आफताब को फाइनेंस किया था। गत 11 जुलाई को पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के लिए काम करने और हाल में छह पुलिसकर्मियों की हत्या सहित, कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के आरोप में उत्तरप्रदेश के एक निवासी संदीप कुमार शर्मा, उर्फ आदिल को गिरफ्तार किया गया।

- **पुलिस के अनुसार सलीम ने सेना की मुखबरी करने के लिये आईएसआई एजेन्ट आफताब को फाइसेंस किया था।**

एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरनगर का निवासी शर्मा लश्क ए तैयबा के मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसका पर्दाफाश जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है।

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के निवासी मुनीब शाह को भी गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक मुनीर खान ने संवाददाताओं से कहा, हमने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े अपराधों समेत सिलसिलेवार सनसनीखेज अपराधों में संलिप्त रहे एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर के निवासी संदीप कुमार शर्मा उर्फ आदिल और दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के निवासी मुनीब शाह को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि संदीप की गिरफ्तारी आपराधिकता और आतंकवाद के बीच धुंधलाती रेखाओं को दिखाती है। लश्कर-ए-तैयबा शर्मा का अकसर इस्तेमाल करता था और वह इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था कि वह यहां का स्थानीय व्यक्ति नहीं है।

मुख्यमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अजीतपुरा बालाजी से होगी, जो सी ए डी चौराहा होते हुए ब्रह्मपुरी बालाजी तिराहा तक आयोजित किया जाएगा। रोड शो के दौरान अग्रिम पंक्ति में महिला एवं युवा शक्ति विशेष रूप से शामिल रहेगी।

ट्रंप ने हंगरी को रुस से तेल, गैस खरीदने की छूट दी

वाशिंगटन, 08 नवंबर। अमेरिका रूस से तेल और गैस खरीदने को लेकर हंगरी पर एक साल तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

बीबीसी ने वाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हंगरी को रूसी तेल और गैस की खरीद को लेकर एक साल के लिए प्रतिबंधों से छूट दे दी है।

गौरतलब है कि ट्रम्प ने कहा था कि वह हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन को छूट देने के मुद्दे पर विचार करेंगे। ओर्बन को ट्रंप का करीबी माना जाता है, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान हंगरी ने रूस के साथ भी अच्छे संबंध विकसित किये हैं।

ट्रम्प ने ओर्बन से साथ व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान कहा था कि हंगरी को छूट देने के मुद्दे पर पर विचार किया जा रहा है क्योंकि उसके लिए अन्य क्षेत्रों से तेल और गैस प्राप्त करना बहुत मुश्किल है।

- **अमेरिका ने हंगरी पर रुसी तेल व गैस खरीद पर लगे प्रतिबंधों को एक साल आगे सरकाया।**

वहीं बीबीसी ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि यह छूट सिर्फ एक साल के लिए है। अमेरिका की ओर से हंगरी को मिली यह छूट ओर्बन के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्होंने कहा था कि प्रतिबंध उनके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे।

पेंशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश बृजमोहन की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता 30 जून 2023 को रिटायर हुआ और उसे मासिक पेंशन जारी कर दी गई। वहीं ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन के लिए जीपीओ और सीपीओ सहित, लीव इनकैशमेंट का आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन विभाग ने इन परिलाभों का भुगतान परिवादी को नहीं किया। करीब एक साल की देरी से मई, 2024 में उसे पीएल का भुगतान किया और उसके बाद गत जुलाई माह में ग्रेच्युटी और कम्युटेशन हुआ। याचिका में कहा गया कि इस देरी के लिए राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ता को कोई ब्याज नहीं दिया गया।

- **हाई कोर्ट ने प्रमुख वन सचिव व प्रमुख मुख्य वन संरक्षक से जवाब मांगा।**

क्या भाजपा का सवर्ण वोट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मतदान कर रहे हैं, जिससे भाजपा की विपक्षी वोटों के बंटवारे की उम्मीद पर पानी फिर गया है।

इसी तरह, प्रशांत किशोर की जन सुराज के उम्मीदवारों से मिलने वाली बहुचर्चित चुनौती भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि किशोर का अभियान भले ही व्यापक और जोशपूर्ण हो, लेकिन उसने न तो एनडीए के वोट बैंक में कोई खास सेंध लगाई है, और न ही महागठबंधन के आधार को ही प्रभावित किया है।

भाजपा खेमे के भीतर भी गृह मंत्री अमित शाह के बड़बोलेपन से भरे उस बयान को लेकर बेचैनी है, जिसमें उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ दावा किया कहा था कि भाजपा 160 सीटों के साथ अगली सरकार बनाएगी। आत्मविश्वास दर्शाने के उद्देश्य से दिये गये इस बयान ने जेडीयू के कुछ नेताओं को नाराज़ कर दिया, जिससे दोनों सहयोगी दलों के बीच तनाव बढ़ गया। शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सुलह के प्रयास शाह के बयान से हो चुके नुकसान की भरपाई नहीं कर सके। एक वरिष्ठ एनडीए नेता के शब्दों में, यह प्रयास बहुत देर से हुआ और जो धारणा बन चुकी थी, उसे खत्म नहीं किया जा सका।

इसी बीच, समस्तीपुर से आई खबरों ने राज्य में मतदान वाले दिन को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, एक स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में गड़बड़ी और सार्वजनिक स्थान पर बड़ी संख्या में वीवीपैट स्लिप मिलने की शिकायत हुई है, जिससे राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। चुनाव अधिकारियों ने इन मामलों की जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और इसे भुनाते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन पर लापरवाही और संभावित हेरफेर के आरोप लगाए हैं। मतदान में अब कुछ ही समय बाकी हैं और दोनों गठबंधन आख़िरी समय में नुक़सान की भरपाई की कोशिशों में जुटे हैं। भाजपा के लिए ऊंची जातियों के समर्थन में कमी आना और ओवैसी व किशोर जैसे संभावित वोट बाँटने वाले नेताओं का असर न दिखना, चुनावी गणित को उलझा रहा है। जैसे-जैसे बिहार में दूसरा चरण करीब आ रहा है, एनडीए की राह उसकी आशाओं की अपेक्षा, कहीं ज्यादा कठिन लग रही है, जबकि महागठबंधन सत्तारूढ़ गठबंधन की रणनीति में उभरती दरारों से लाभ उठाने की उम्मीद कर रहा है।

भला लगे या बुरा, राष्ट्रीय गान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने यह साजिश भांप ली और बंकिम को चेताया। राजा ने उन्हें अपने विशाल, एकांत महल में शरण दी, जो जंगलों से घिरा हुआ था और जहाँ बंगाल, बिहार और ओडिशा के "तांत्रिकों" का जमावड़ा होता था।

बंकिम वहाँ रहे। अक्सर वे जंगल में घूमने निकलते थे। उन्होंने कुछ पुराने, जर्जर मंदिर खोजे, कुछ आधे ज़मीन में दबे हुए, कुछ गुफाओं में छिपे हुए। इन मंदिरों में काली, दुर्गा और जगद्धात्री की मूर्तियाँ थीं, कभी भयानक रूप में, कभी सौम्य रूप में।

जमींदार बाड़ी कंटीली झाड़ियों और विशाल वृक्षों के एक विशाल जंगल के किनारे पर थी, जिसने एक अभेद्य किले का वातावरण बना दिया था। इस जंगल के अंदर, मंदिर बिखरे हुए थे, कुछ दरारों में और कुछ ज़मीन के नीचे। वहाँ, एकांत, दूरस्थ, अंधेरी भूमि की अपनी यात्राओं में, बंकिम को अपने जीवन और समकालीन दृश्यों की शृंखला की एक अजीब अनुभूति हुई।

एक मंदिर में उन्हें देवी काली की एक प्रतिमा मिली, जिसका स्वरुप कठोर और विकराल था। दूसरे मंदिर में उन्हें काली के भीतर दुर्गा की छवि मिली, लेकिन, उनके साथ देवी सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश और कार्तिक भी थे।

फिर उस घने जंगल में घूमते हुए बंकिम चंद्र को एक और मंदिर मिला, जिसमें दुर्गा की प्रतिमा थी और ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ समय पहले तक इसकी पूजा होती रही होगी।

- **उन्होंने अपने मित्रों से साझा किया था कि उनके गान का महत्व देश उनकी मृत्यु के बाद समझेगा।**
- **1896 में ऐसा ही हुआ, उनकी मृत्यु के बाद। यह गान देश प्रेम का प्रतीक बना, अंग्रेजों से लड़ाई में और शहीदों का प्रेरणा स्रोत बना।**
- **यह गाना सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन सत्र में गाया था और उनकी भतीजी ने भी अन्य सत्रों में इसे गाया था।**
- **उस काल में स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से हिंदू ही थे और किसी ने इस गान को अप्रिय नहीं महसूस किया।**
- **पर, 1930 के अर्धदशक में जिन्ना ने इस गान पर आपत्ति की, मतभेद न पनपे इस दृष्टि से नेहरू जी, जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, ने केवल दो छंदों का ही प्रयोग करने का निर्णय लिया।**

देवी काली, दुर्गा और जगतधात्री के अनेक मंदिरों वाले उस विशाल जंगल में बंकिम का मन देवी के विभिन्न अवतारों और देश की स्थिति में डूब गया।

बंकिम ने अपने मन में जगतधात्री की छवि को देवियों की रानी के भव्य वैभव में देखा। दूसरी छवि में उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति देखी, जहाँ, काली लगभग बिना कुछ पहने, खोपड़ियों के साथ एक मृत शिव के ऊपर खड़ी थीं।

अंतिम छवि में उन्होंने देवी को दुर्गा के रुप में, पूरे वैभव में, विशाल सिंह पर सवार, सभी आयुधों से सम्पन्न और एक शक्तिशाली राक्षस का वध करने की स्थिति में देखा। यह देवी की वही छवि थी, जिसे उन्होंने अपने पैतृक घर में दुर्गा पूजा के दौरान देखा था।

इन मूर्तियों को देखकर उनके मन में भारत माता की दशा के प्रतीक रूप उभरने लगे, जो मानो, आर्यावर्त या भारत की देवी माँ की दुर्दशा को दर्शाती थी।

बंकिम चंद्र उन्हीं दिनों अपनी पत्रिका "बंगदर्शन" का संपादन कर रहे थे। उन्होंने "वंदे मातरम्" कविता वहीं लिखी, पर तत्काल प्रकाशित नहीं की। बाद में जब यह कविता प्रकाशित हुई, तो उस पर विवाद उठ खड़ा हुआ।

कई लोगों ने कहा कि कविता अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ है और सामान्य बंगाली में नहीं लिखी गई। कुछ ने कहा कि यह गाने में भी मधुर नहीं है। लेकिन बंकिम ने किसी की बात नहीं मानी। बंकिम अपनी बात पर अड़े रहे और भाषा के कुछ वास्तविक बिंदुओं को छोड़कर कोई भी बदलाव करने से इन्कार कर दिया।

इसके बजाय, बंकिम हमेशा यह कहते रहे कि जो कोई भी कविता में कोई दोष पाता है, वह उसे न पढ़े। जो कोई भी आहत महसूस करता है, उसे इसका अर्थ समझने की कोशिश करने से दूर रहना चाहिए। और बताया जाता है कि उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों में से कुछ को यह भी बताया था कि कविता का महत्व उनकी मृत्यु के बाद ही स्पष्ट होगा। उनके जाने के अनेक वर्षों बाद भी, कविता पूरे देश की कल्पना पर छाई रही।

बंकिम की मृत्यु के कई वर्ष बाद, 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम् गाया। बाद में टैगोर की भतीजी ने भी इसे एक और अधिवेशन में गाया। कहा जाता है कि इसकी धुन यदु भट्ट नामक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार ने बनाई थी।

यह गीत धीरे-धीरे आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बन गया। ब्रिटिश हुकूमत से टकराते क्रांतिकारी "वंदे मातरम्" गाते हुए फाँसी पर झूल गए, गोलियाँ खाईं। इस गीत ने उन्हें साहस और जोश दिया। अंग्रेज हुकूमत ने इस गीत के गाने और बोलने तक पर प्रतिबंध लगा दिया।

आज़ादी की लहर में यह गीत राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति का पर्याय बन गया। शुरुआती वर्षों में स्वतंत्रता आंदोलन मुख्यतः हिंदू समाज के नेतृत्व में था, इसलिए गीत के उन अंशों को लेकर किसी को आपत्ति नहीं थी।

कांग्रेस के अधिवेशनों में "वंदे मातरम्" हर बार गाया जाता था। परंतु 1930 के दशक में, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस गीत का विरोध किया। तब कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने समाधान के तौर पर केवल पहले दो पद गाने का सुझाव दिया।

लेकिन सच्चाई यह है कि अगर केवल पहले दो पद ही गाए जाएँ, तो गीत अधूरा और संदर्भहीन हो जाता है।

इस गीत पर आखिरी बात यही कही जा सकती है -

अगर गाना है, तो पूरा गाओ।

अगर नहीं गाना चाहते, तो मत गाओ।

लेकिन कृपया इसे टुकड़ों में मत बाँटो, क्योंकि ऐसा करना इसकी आत्मा, इसके समय और इसके रचयिता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीनों के साथ अन्याय होगा।

बंकिमचंद्र वह व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेजों के सबसे ताक़तवर समय में भी सिर झुकाने से इनकार किया। वे कभी अपनी रचना को तोड़ने या कमज़ोर करने की अनुमति नहीं देते।

जीएसटी कम होने के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरसों महंगे दामों पर खरीदने पड़ी, जिसका बोझ उन्होंने उपभोक्ताओं पर डाल दिया। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल बाज़ारों का असर भी पड़ा। पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के वैश्विक दाम भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति बाधाओं की वजह से ऊँचे बने हुए हैं, ख़ासकर ब्लैक सी क्षेत्र में जारी संघर्ष और रेड सी मार्ग में परिवहन मुश्किलों के कारण। चूंकि सरसों का तेल इन्हीं खाद्य तेलों से प्रतिस्पर्धा करता है, इसलिए इसकी कीमतें भी वैश्विक रुझानों के साथ बढ़ जाती हैं।

चीनी का मामला भी कुछ ऐसा ही है। भारत की शुगर मिलें अब अपने गन्ने के उत्पादन का बड़ा हिस्सा एथनॉल बनाने में इस्तेमाल कर रही हैं, जो सरकार की बायोफ्यूल नीति का हिस्सा है। जहाँ, इससे तेल आयात में कमी आती है, वहीं खुले बाज़ार में चीनी की आपूर्ति घट जाती है।

अक्टूबर-नवंबर के त्योहारी मौसम में मांग के कारण स्टॉक पर और दबाव पड़ता है। कथित रुप से कई मिलों ने स्टॉक रोक रखे हैं, ताकि त्योहारों के बाद ऊँचे दाम पर बेच सकें। नतीजतन, टैक्स कटौती के बावजूद चीनी के दाम नीचे नहीं आए हैं।

गेहूं और उससे बने उत्पाद जैसे आटा को भी जीएसटी राहत का फायदा नहीं मिला है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बड़ी मात्रा में गेहूं की ख़रीद की है, जिससे निजी व्यापारियों के पास कम अनाज बचा। इसका सीधा असर थोक कीमतों पर पड़ा और पैकेट वाले आटे की लागत बढ़ गई। अनियमित मानसून और कटाई के समय आई असमय बारिश ने उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे प्रमुख राज्यों में फसल की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचाया।

इन आपूर्ति संबंधी समस्याओं के अलावा, अर्थव्यवस्था पर व्यापक महंगाई का दबाव भी है। पिछले दो वर्षों में, डीज़ल, खाद, बिजली और पैकेजिंग सामग्री तक, इनपुट लागतों में लगातार वृद्धि हुई है। परिवहन और लॉजिस्टिक खर्च भी ऊँचे बने हुए हैं, क्योंकि डीज़ल की कीमतें कच्चे तेल की गिरावट के साथ नहीं घटीं। खुदरा व्यापारी, जिन पर खर्च का बोझ बढ़ गया है, टैक्स कटौती से मिलने वाले छोटे लाभ को ग्राहकों तक पहुँचाने के बजाय अपने मुनाफे को सुरक्षित रखना पसंद कर रहे हैं, ताकि भविष्य की अस्थिरता से बच सकें।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीएसटी दरों में कटौती केवल अंतिम खुदरा मूल्य के टैक्स हिस्से को प्रभावित करती है, उत्पादन या वितरण लागत को नहीं। उदाहरण के लिए, पाँच प्रतिशत जीएसटी घटने से 100 रुपए के उत्पाद पर केवल पांच रुपए की बचत होती है। लेकिन अगर उत्पादन लागत 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो गई है, तो भी अंतिम कीमत बढ़ेगी। यानी टैक्स नीति महंगाई के असर को थोड़ा कम कर सकती है, पर लागत आधारित महंगाई के बड़े रुझान को उलट नहीं सकती।

स्थानीय और वैश्विक कारणों के इस मिलेजुले प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं को राहत क्यों नहीं मिली। भारत में खाद्य महंगाई हमेशा आपूर्ति झटकों और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित रहती है। यहां तक कि जिन वस्तुओं की देश में प्रचुरता है, उनकी कीमतें भी वैश्विक संकेतों से तय होती हैं। हालिया जीएसटी अनुभव ने यह बात दोबारा साबित की है कि अप्रत्यक्ष कर नीति की ताकत सीमित होती है और वह खाद्य महंगाई पर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकती।

फिलहाल, भारतीय परिवार एक परिचित सबक फिर से सीख रहे हैं, सरकारें भले टैक्स घटा दें, पर असली फैसला बाज़ार करता है। जब तक मौसम स्थिर नहीं होता, वैश्विक आपूर्ति सुधरती नहीं और घरेलू परिवहन लागत घटती नहीं, तब तक रसोई का बजट दबाव में ही रहेगा, जीएसटी राहत हो या न हो।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908